



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 28 मार्च, 2001/7 चैत्र, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 मार्च, 2001

संख्या पी०बी० डब्ल्यू०(बी)३(४)११/९८.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश यान्त्रिक यान (पुल पथ कर) अधिनियम, १९६८ (१९६९ का २०) की धारा २ के खण्ड (क) के साथ पठित धारा ३ की उप-धारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न प्रथम और द्वितीय अनुसूची का निम्न रीति में १-४-२००१ से संशोधन करते हैं अर्थात् :—

प्रथम अनुसूची का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश यान्त्रिक यान (पुल पथ कर) अधिनियम, १९६८ (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है), से संलग्न प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या १ से ४४ के सामने आए पुलों का लोप किया जाएगा ।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.—मूल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची में क्रम संख्या १ से ५ पर दर्शित यान्त्रिक यानों और कर की दरों का लोप किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

वित्तायुक्त एवं सचिव ।

संख्यांक 3)" जो आज दिनांक 28 मार्च, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2001 है ।

संक्षिप्त
नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां जिनका योग 59,77,34,51,000 रुपए (उनसठ अरब, सतहत्तर करोड़, चौतीस लाख, इक्यावन हजार रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2001-2002 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

हिमाचल
प्रदेश राज्य
की संचित
निधि में से
वित्तीय वर्ष
2001-
2002
के लिए
59,77,34,
51,000
रुपए की
राशि जारी
करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभासित	जोड़
		रुपए	रुपए	रुपए
1	विधान सभा (राजस्व) (पूंजी)	5,23,73,000 85,00,000	12,12,000 —	5,35,85,000 85,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	3,41,65,000	1,43,51,000	4,85,16,000
3	न्याय प्रशासन और (राजस्व) निर्वाचन (पूंजी)	29,81,57,000 1,75,00,000	5,85,15,000 —	35,66,72,000 1,75,00,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	45,64,91,000 35,00,000	2,44,71,000 —	48,09,62,000 35,00,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	1,41,75,51,000 6,76,000	— —	1,41,75,51,000 6,76,000
6	आवकारी और कराधान (राजस्व) (पूंजी)	14,71,84,000 2,00,000	— —	14,71,84,000 2,00,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) (पूंजी)	1,84,98,74,000 1,11,80,000	— —	1,84,98,74,000 1,11,80,000
8	शिक्षा (राजस्व) (पूंजी)	7,87,52,00,000 56,25,01,000	— —	7,87,52,00,000 56,25,01,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व) (पूंजी)	2,47,76,51,000 14,59,05,000	— —	2,47,76,51,000 14,59,05,000
10	लोक निर्माण-भवन (राजस्व) (पूंजी)	1,55,19,94,000 2,30,00,000	— —	1,55,19,94,000 2,30,00,000
11	कृषि (राजस्व) (पूंजी)	75,84,44,000 28,70,00,000	— —	75,84,44,000 28,70,00,000
12	उद्यान (राजस्व) (पूंजी)	48,97,25,000 5,10,00,000	— —	48,97,25,000 5,10,00,000
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व) (पूंजी)	82,34,11,000 34,57,30,000	— —	82,34,11,000 34,57,30,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व) (पूंजी)	57,17,55,000 45,70,000	— —	57,17,55,000 45,70,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (राजस्व) उप योजना (पूंजी)	1,08,63,17,000 24,50,07,000	— —	1,08,63,17,000 24,50,07,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व) (पूंजी)	2,38,60,75,000 1,41,00,000	— —	2,38,60,75,000 1,41,00,000
17	सड़कें और पुल (राजस्व) (पूंजी)	2,43,82,98,000 1,51,03,35,000	— —	2,43,82,98,000 1,51,03,35,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व) (पूंजी)	31,03,43,000 7,00,000	— —	31,03,43,000 7,00,000

1	2	3		
		रुपए	रुपए	रुपए
19	सामाजिक सुरक्षा और (राजस्व)	83,75,99,000	—	83,75,99,000
	कल्याण (पोषाहार सहित) (पूँजी)	1,87,02,000	—	1,87,02,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	82,99,58,000	—	82,99,58,000
21	सहकारिता (राजस्व)	12,41,47,000	—	12,41,47,000
	(पूँजी)	95,28,000	—	95,28,000
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	10,82,35,000	—	10,82,35,000
	(पूँजी)	28,20,92,000	—	28,20,92,000
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	1,10,58,08,000	—	1,10,58,08,000
	(पूँजी)	1,15,55,01,000	—	1,15,55,01,000
24	मृदण और लेखन (राजस्व)	5,27,04,000	—	5,27,04,000
	सामग्री			
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व)	28,75,88,000	—	28,75,88,000
	(पूँजी)	12,80,00,000	—	12,80,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व)	1,92,70,000	—	1,92,70,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	23,63,54,000	—	23,63,54,000
	(पूँजी)	82,00,000	—	82,00,000
28	जलापूर्ति, मफाई, आवास (राजस्व)	2,77,89,68,000	—	2,77,89,68,000
	और नगर विकास (पूँजी)	1,01,52,16,000	—	1,01,52,16,000
29	वित्त (राजस्व)	4,83,53,90,000	11,58,94,92,000	16,42,48,82,000
	(पूँजी)	11,10,01,000	3,26,19,43,000	3,37,29,44,000
30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)	16,01,17,000	—	16,01,17,000
	(पूँजी)	58,01,000	—	58,01,000
31	जन-जातीय विकास (राजस्व)	1,65,06,97,000	—	1,65,06,97,000
	(पूँजी)	80,61,79,000	—	80,61,79,000
	कुल जोड़	44,82,34,67,000	14,94,99,84,000	59,77,34,51,000
	(राजस्व)	38,05,18,43,000	11,68,80,41,000	49,73,98,84,000
	(पूँजी)	6,77,16,24,000	3,26,19,43,000	10,03,35,67,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपाय करने के लिए पुरस्थापित है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

28 मार्च, 2001.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन0 ए0 सी0 (1)-1/2001]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2001 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) BILL, 2001

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2001-2002.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2001.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of Rs. 59,77,34,51,000 (Fifty nine hundred and seventy seven crores, thirty four lakhs, fifty one thousands rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2001-2002 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

Issue of a sum of Rs. 59,77,34,51,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2001-2002.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 De- mand No.	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Conso- lidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue)	5,23,73,000	12,12,000	5,35,85,000
	(Capital)	85,00,000	—	85,00,000
2	Governor and Council of Ministers (Revenue)	3,41,65,000	1,43,51,000	4,85,16,000
3	Administration of Justice (Revenue)	29,81,57,000	5,85,15,000	35,66,72,000
	and Election (Capital)	1,75,00,000	—	1,75,00,000
4	General Administration (Revenue)	45,64,91,000	2,44,71,000	48,09,62,000
	(Capital)	35,00,000	—	35,00,000
5	Land Revenue and District Administration (Revenue)	1,41,75,51,000	—	1,41,75,51,000
	(Capital)	6,76,000	—	6,76,000
6	Excise and Taxation (Revenue)	14,71,84,000	—	14,71,84,000
	(Capital)	2,00,000	—	2,00,000
7	Police and Allied Organisations (Revenue)	1,84,98,74,000	—	1,84,98,74,000
	(Capital)	1,11,80,000	—	1,11,80,000
8	Education (Revenue)	7,87,52,00,000	—	7,87,52,00,000
	(Capital)	56,25,01,000	—	56,25,01,000
9	Health and Family Welfare (Revenue)	2,47,76,51,000	—	2,47,76,51,000
	(Capital)	14,59,05,000	—	14,59,05,000
10	Public Works—Building (Revenue)	1,55,19,94,000	—	1,55,19,94,000
	(Capital)	2,30,00,000	—	2,30,00,000
11	Agriculture (Revenue)	75,84,44,000	—	75,84,44,000
	(Capital)	28,70,00,000	—	28,70,00,000
12	Horticulture (Revenue)	48,97,25,000	—	48,97,25,000
	(Capital)	5,10,00,000	—	5,10,00,000
13	Irrigation and Flood Control (Revenue)	82,34,11,000	—	82,34,11,000
	(Capital)	34,57,30,000	—	34,57,30,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries (Revenue)	57,17,55,000	—	57,17,55,000
	(Capital)	45,70,000	—	45,70,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan (Revenue)	1,08,63,17,000	—	1,08,63,17,000
	(Capital)	24,50,07,000	—	24,50,07,000
16	Forest and Wild Life (Revenue)	2,38,60,75,000	—	2,38,60,75,000
	(Capital)	1,41,00,000	—	1,41,00,000
17	Roads and Bridges (Revenue)	2,43,82,98,000	—	2,43,82,98,000
	(Capital)	1,51,03,35,000	—	1,51,03,35,000
18	Supplies, Industries and Minerals (Revenue)	31,03,43,000	—	31,03,43,000
	(Capital)	7,00,000	—	7,00,000
19	Social Security and Welfare (including Nutrition) (Revenue)	83,75,99,000	—	83,75,99,000
	(Capital)	1,87,02,000	—	1,87,02,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development	(Revenue)	82,99,58,000	—	82,99,58,000
21	Co-operation	(Revenue)	12,41,47,000	—	12,41,47,000
		(Capital)	95,28,000	—	95,28,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	10,82,35,000	—	10,82,35,000
		(Capital)	28,20,92,000	—	28,20,92,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	1,10,58,08,000	—	1,10,58,08,000
		(Capital)	1,15,55,01,000	—	1,15,55,01,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	5,27,04,000	—	5,27,04,000
25	Road and Water Transport	(Revenue)	28,75,88,000	—	28,75,88,000
		(Capital)	12,80,00,000	—	12,80,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	1,92,70,000	—	1,92,70,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue)	23,63,54,000	—	23,63,54,000
		(Capital)	82,00,000	—	82,00,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	2,77,89,68,000	—	2,77,89,68,000
		(Capital)	1,01,52,16,000	—	1,01,52,16,000
29	Finance	(Revenue)	4,83,53,90,000	11,58,94,92,000	16,42,48,82,000
		(Capital)	11,10,01,000	3,26,19,43,000	3,37,29,44,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	16,01,17,000	—	16,01,17,000
		(Capital)	58,01,000	—	58,01,000
31	Tribal Development	(Revenue)	1,65,06,97,000	—	1,65,06,97,000
		(Capital)	80,61,79,000	—	80,61,79,000
	Grand Total		44,82,34,67,000	14,94,99,84,000	59,77,34,51,000
	(Revenue)		38,05,18,43,000	11,68,80,41,000	49,73,98,84,000
	(Capital)		6,77,16,24,000	3,26,19,43,000	10,03,35,67,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India, to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2000-2001.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 28th March, 2001.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

[Finance Department File No. Fin. A. C. (1) 1/2000]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No 2) Bill, 2001, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.